

गोरक्षणी भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 263 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, मंगलवार, 23 मार्च 2021, मूल्य ₹. 1.50

एक नज़र...

अयोध्या में बनेगी
श्री राम यूनिवर्सिटी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दिवेश शर्मा ने अयोध्या में श्री राम यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा की है। शर्मा के पास उच्च शिक्षा मंत्रालय भी है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव निजी क्षेत्र से आया है और इस यूनिवर्सिटी के 2022 तक शुल्क होने की संभवता है।

आईआईएम
कोलकाता निदेशक
अंजू सेठ का इस्टीफा

नई दिल्ली। आईआईएम कोलकाता की निदेशक अंजू सेठ ने इस्टीफा दे दिया है। निदेशक के रूप में अंजू सेठ का अधीक्षी 1 वर्ष का कार्यकाल शेष था, लेकिन चेयरमैन से हुए विवाद के उपरांत उन्होंने अपने पद से इस्टीफा दे दिया। वह आईआईएम कलकाता की पहली महिला निदेशक थी।

वामपंथी मोर्चे की
प्रचारक शैलजा के
खिलाफ शिकायत

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूटीएफ के एन्कुलम जिले के प्रमुख ने मुख्य चुनाव आयुक्त से वाम लक्तांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की स्टार प्रचारक और राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के लिए शैलजा के खिलाफ शिकायत की गई है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन किया है।

श्रीनगर-जम्मू
राजमार्ग पर एकत्रफा
यातायात जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर बारिश के एकत्रफा यातायात की अनुमति दी गई। राज्य के 270 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग पर फंसे भारी बाहुलों को आज श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति दी गई। इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर के एंटिटारिक मुग्ल रोड और अंतर्राज-किश्तवाड़ी मार्ग बंद पड़ा है।

मतदान के 72 घंटे
पहले बाइक रैली
निकालने पर लगी रोक

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदान से 72 घंटे पहले संबंधित क्षेत्र में बाइक रैली पर रोक लगा दी गई है। ताकि राजनीतिक दलों के लाग भवानदाताओं को प्रभावित न कर सके। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस समय पश्चिम बंगाल, कर्णाटक, तमिलनाडु, पुरुद्वेरी और असम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं।

परम बीर सिंह चिट्ठी 'बम' प्रकरण पवार ने गृहमंत्री को दी क्लीन चिट, अस्पताल में थे देशमुख, वाझे से नहीं की मुलाकात

(एजेंसी)

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकोंपा) के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह

हिन्दू की पत्नी का बयान दर्ज करने आवास पहुंची एनाईए

संसद ने भी उठाना चाहिए

मुंबई। व्यापारीय मनसुख हिन्दू की मौत को जांच के दिन मामला दर्ज करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएआईए) ने उत्तर पाली और अचूल लोगों के बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास का पहाड़ी।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त रिश्ते मुद्रुदे को उठाया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए सदन में नावेजाओ जाए। प्रश्नकाल के दौरान, जब जावड़ेकर की उत्तरके मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने की आई, तो उन्होंने कहा कि मैं सचालन नहीं सुन सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में, मंत्री पूर्व पुलिस प्रमुख के हुए कहा है कि अपरें पुलिस बम लगा रही है जो पहले आतंकवादी किया करते हुए रहा। अप्रैल तक, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए निर्देश देने का उत्तरु अनुरोध किया गया है।

ये मुद्रा संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया। राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को अनिल देशमुख के बर्खास्त करने के लिए

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बाद उनकी
पली बुशरा बीबी भी हुई कोरोना संक्रमित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पली बुशरा बीबी भी कोरोना संक्रमित हो गई है। इमरान में संक्रमण की पुष्टि के कुछ घंटे बाद ही बुशरा बीबी के संक्रमित होने की जानकारी समाप्त आई। इमरान की पाठी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाफ के फैजल जावेद ने बुशरा बीबी के संक्रमित होने की पुष्टि करते हुए पीएम और उनके पली तक जल्द स्वस्थ होने की दुआ की। कोरोना की चीज़ी वैक्सीन लगावने के दो दिन बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मामलों पर पाकिस्तानी पीएम के विशेष सहायक फैजल सुलतान ने यह जानकारी दी। इमरान ने घर पर ही खुद को क्रांतिकारी लिया है। वह बीड़ियों कांपेंसिंग के माध्यम से घर से काम करना रखेंगे। इमरान के संक्रमित होने की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके शोध स्वच्छ होने की कामना की। इमरान के प्रवक्ता डॉ. शहबाज गिल ने बताया कि पीएम को बुशरा और खानसी है। टीकाकरण के बाद पीएम के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के दूसरे या तीसरे हमें एंटीबोडी बनती है। उन्हें दो दिन पहले ही वैक्सीन में तल्पनी डोज दी गई थी और वह संक्रमित हो गए। इसलिए टीके के प्रभाव को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है।

उधर, पाकिस्तान सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि पीएम टीकाकरण के पहले ही कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे थे। देश में कोरोना ऑपरेशन पर बनाए गए मंत्री समूह के प्रमुख असद उमर ने भी कहा है कि टीकाकरण के पहले ही कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसलिए अम लोगों को सलाह है कि टीकाकरण कराएं। पिछले वर्ष कई पाकिस्तानी सांसद कोरोना संक्रमित हो गए थे, इनमें प्रमुख मुत्तहिदा कौमी मूवेंट पाकिस्तान (एस्यूयूप-पी) के नेता और सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री संव्यव अमीनुल हक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ (पीएमएल-एन) के प्रवक्ता मरहम औरंजेब, तेल मंत्री शेख राशिद अहमद थे। पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी भी कोरोना संक्रमित हो गए थे।

बाइंडन को बताया हृत्यारा तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा- आप स्वस्थ रहें यही कामना करता हूं

मास्को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइंडन द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्हाइटमोर पूर्तिन को हृत्यारा बताए बयान के बाद अब पुतिन ने भी उन्हें जवाब दिया है लेकिन बेहद शालीनता के साथ। उन्होंने कहा है कि वो बाइंडन के बेहद स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शुक्रवार या फिर सोमवार को बात करेंगे। रूसी अखबार स्पूनिनकी को मुत्तहिदा कौमी मूवेंट पाकिस्तान (एस्यूयूप-पी) के नेता और सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री संव्यव अमीनुल हक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ (पीएमएल-एन) के प्रवक्ता मरहम औरंजेब, तेल मंत्री शेख राशिद अहमद थे। पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी भी कोरोना

साथ

उत्तर

दिल्ली में पिछले दरवाजे से शायन चलाने की कोशिश है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक: कांग्रेस

नई दिल्ली (बेबवार्ता)। कांग्रेस ने 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021' का विधेयक करते हुए सोमवार को लोकसभा में दरवा किया कि इस 'असंवेधानिक विधेयक' के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली में पिछले दरवाजे से शायन चलाने की कोशिश कर रही है। संसद के निचले सदन में इस विधेयक पर चर्चा का शुरूआत करते हुए कांग्रेस के मीणीपत्रिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकलत करने वाली भाजपा और केंद्र की उचिती मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा, "2003 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकर्णी आडवाणी ने संविधान में 102वां संशोधन संबंधी विधेयक को पेश किया था। इन विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उद्देश्य कि नई दिल्ली इलाके को छोड़कर शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।"



का उद्देश्य था कि नई दिल्ली इलाके को छोड़कर शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। तिवारी ने कहा कि अब भाजपा की सरकार 18 साल बाद यह विधेयक लेकर आई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने वाला है। लेकिन अब उससे

जी किशन रेही से मुख्यातिव होते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा कहा, "मंत्री जी, कृपया आडवाणी जी है। कांग्रेस नेता ने कहा, "इस विधेयक में आपने (केंद्र) कह दिया कि दिल्ली सरकार का मलतब उप राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं और उप राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं।" उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना था। पीड़िता 16 वर्षीय किशोरी मां के साथ शास्त्री पार्क इलाके में बुलंद मस्जिद के पास रहती है। उसके पिता का निधन हो चुका है। किशोरी एक स्कूल में अठवां की छात्रा है। पीड़िता के अनुसार, उसका परिवार पहले गांधी राज के कैलाश नार में रहता था। उसकी मां की सहेली शास्त्री पार्क में रहती है। करीब तीन महीने पहले वह अपनी मां के साथ उनकी सहेली के घर गई थी, जहां बातचीत के दौरान उनकी दिल्ली में रहने के लिए गई है। इसके बाद पीड़िता को परिवार भी शास्त्री पार्क इलाके में आकर रहने लगा। किशोरी रोज मां की सहेली की बेटी से दूर्योग पड़ने जाने लगी। अपरोप है कि मां की सहेली का पति मो. कालिम मौका मिलने ही उससे छेड़खाने करता था। कई बार जब किशोरी की मां काम पर चली जाती थी तो आरोपी पीड़िता के कमरे में आकर उससे छेड़खान करता था। साथ ही उसकी खिलाफ भ्रष्ट अब भरत के लिए उस पर दबाव बना रहा है। अपरोप है कि पांच वर्षों से आरोपी ने बाइक खिलाफ भ्रष्ट अब मोनू ने भरत से अपने साथ लेकर जीवन की चुनी हुई दूसरे से मिलने-जुलने लगा। उन्होंने तीन साल पहले फेसबुक पर लगे खून को देखकर भरत की हत्या कर दी। पुलिस के दूसरे से मिलने-जुलने की तो उन्हें अपने दोस्त की हत्या करने की बात कही। पुलिस उसे तूरंत लेकर घटना स्थल पर पहुंची और भरत का शब बरामद किया। आरोपी मोनू ने पुलिस को बताया कि भरत और उसके बीच यौन संबंध था। लेकिन, भरत अब यौन संबंध के लिए उलगातार उस पर दबाव बनाने के लिए जाने लगा। साथ ही उसे धमकी भी देता था। इससे मोनू की शारीरिक जिंदगी खत्म हो गई है। मोनू ने भरत से पोंछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई और सोमवार तड़के करीब चार बजे मोनू ने त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर-17 में वसुंधरा रोड के किनारे पर अपने साथ लेकर उसके पापड़े पर लगे खून को देखकर भरत की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी मोनू त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर-32 में रहता है। इसी की वजह से आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या करने की बात कही। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आरोपी 22 वर्षीय मोनू से पूछताछ कर रामलीला के ब्लॉक नंबर-1 में रहता था। परिवार में माता-पिता, तीन भाई और एक बच्चा हैं। भरत एक अनॉलाइन कंपनी में डिलीवरी वर्कर, हत्या के बाद आरोपी

2003 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकर्णी आडवाणी ने संविधान में 102वां संशोधन संबंधी विधेयक को पेश किया था। इन विधेयकों को दरवाजे से दिल्ली में रहने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

तिवारी ने कहा कि साल 2018 में उच्चतम न्यायालय ने यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। तिवारी ने कहा कि अब भाजपा की सरकार 18 साल बाद यह विधेयक लेकर आई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की अधिकार को छीनने वाला है। लेकिन अब उससे

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ विधेयकों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है।

प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और उपर विधेयक के बाय-अधिकार क्षेत्र के द्वारा यह विधेयक को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है। तिवारी ने कहा कि अब भरत को अपने साथ लेकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने विध

संपादकीय

उन्हें निजीकरण से डर लगता है

देश के बैंकिंग सेक्टर में इन दिनों खासा उथल-पुथल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक युनियन्स (यूएफबीयू) के बैनर तले सोमवार और मंगलवार को 1 सरकारी बैंकों के कम्पनियों ने हड़ताल की, और चेतावनी दी है कि इस दिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे अनिश्चितकालीन एंटोलेन पर उत्तरने को बाध्य होंगे। इस हड़ताल की वजह केंद्र सरकार का है लेनाहै, जिसमें उसने कहा था कि आईडीबीआई सहित वह दो अन्य सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला तोतारमण ने भरोसा दिया है कि ऐसा किए जाने के बावजूद बैंककर्मियों के तरीं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मगर अतीत की घटनाएं बैंकमंचारियों को कहीं अधिक परेशान कर रही हैं। अपने देश में सबसे पहले अतीतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जिसके बाद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ। फिर जुलाई, 1969 में 14 अन्य बैंकों और 1980 में छह बैंकों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया। किन 1990 के दशक में 'वाशिंगटन कन्सेन्स' के तहत केंद्र सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ने लगी, जिसका लब्बोत्तुआब यह है कि बाजार को जागे बढ़ाया जाए और अर्थव्यवस्था में सरकार का दखल कम से कम हो। उससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलने लगा और सरकारी क्षेत्र पिछड़ा गया। हालांकि, इस 'कन्सेन्स' को अपनाने के बाद संसार भर में असमानताएं बढ़ी हैं। सन 2005 के आसपास जाने-माने अर्थशास्त्री पॉल क्रूपैन ने अपने एक लेख में 2001 के आंकड़ों के ब्वाले से बताया था कि अमेरिका जितनी गैर-बराबरी 1920 के दशक में थी, उससे कहीं ज्यादा 2000 दशक में दिखने लगी है। बैंकों के निजीकरण से भी कृष्ण ऐसे ही खतरे बढ़ रहे हैं कि अभी सरकार के पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए जस्व जुटाने के लिए उसने निजीकरण का सहारा लिया है। मगर इससे देश को अधिक तस्वीर कहीं ज्यादा स्थाह हो सकती है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहां गरीबी परसी हुई है। यहां की करीब 90 फीसदी आबादी गरीब है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तो अति-गरीब हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कहीं इन सबकी सुध लेते हैं। इसी कारण गांवों और कस्बों तक में रकारी बैंकों की शाखाएं दिख जाती हैं। चूंकि निजी बैंक सामाजिक बाबदेही से कत्री काटते हैं, इसलिए वे वहीं अपनी शाखा खोलते हैं, जहां उनको फायदा नजर आता है। लॉकडाउन में भी लोगों की जितनी सेवा सरकारी बैंकों ने की, उतनी निजी बैंकों ने नहीं। चूंकि छोटे-छोटे अकाउंट और चलाने में खर्च ज्यादा है, इसलिए जन-धन खाते भी सरकारी बैंकों में ज्यादा खोले गए। नकदी का लेन-देन भी सरकारी बैंकों ने तुलनात्मक रूप ज्यादा किया। यह सब इसलिए संभव हो सका, क्योंकि सरकारी बैंकों ने मकसद लोगों की सेवा करना है, न कि नफे-नुकसान के आधार पर अपनी सेवाएं देना। अगर बैंकों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो भव है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या विश्विद्यालय जैसे बड़े-बड़े स्थानों के वित्तीय लेन-देन में तो वे रुचि लेंगे, लेकिन गरीबों के छोटे-छोटे अकाउंट पर शायद ही उनकी नजर जाए। इससे उन सरकारी योजनाओं के बेअसर होने का खतरा होगा, जिनको फिलहाल सरकारी बैंकों के जरिए अधिर्थों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा, 1969 से पहले निजी के अपनी ही कंपनियों को ज्यादा कर्ज बांटते थे। अब यह खतरा फिर से ढ़ सकता है। इससे अन्य वित्तीय कामों को नुकसान पहुंच सकता है।

यह भी संभव हो सकता है कि यह कानून उसके लिए गले की हड्डी बन जाए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बिहार में राजद बीते विधानसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे को भुनाने में काफी हद तक सफल होता दिखा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन कर उभरा। वह भी हरियाणा सरकार के इस निर्णय पर आक्रामक हो सकता है। यह भी सही है कि बिहार में भाजपा की सहयोगी जदयू, जो खुद भी काफी हद तक क्षेत्रीय पार्टी है, इस मुद्दे पर भाजपा के साथ नहीं खड़ी होगी। अगले साल ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां भी भाजपा का सामना क्षेत्रीय दलों के साथ ही है। ऐसे में वहां भी यह कानून एक मुद्दा बन सकता है।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा में लागू किए गए कानून में मोटे तौर पर चार प्रमुख प्रविधियाँ हैं। पहला, यह कानून 50 हजार रुपये मासिक वेतन तक की नौकरियों पर लागू होता है। दूसरा, इसके दायरे में राज्य में चल रही वे कंपनियाँ, सोसायटी, ट्रस्ट और फर्म आएंगे जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तीसरा, ताल्कालिक तौर पर यह कानून 10 वर्षों के लिए लागू होगा। चौथा, किसी पद के लिए कार्यकुशल कर्मचारी नहीं मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है, मगर इस बारे में निर्णय नियोक्ता कंपनी का नहीं, बल्कि जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी का होगा। इस कानून पर सबसे तीखा विरोध स्थानीय और आर्थिक दोनों ही स्तर के अधिकांश औद्योगिक संगठनों ने किया है। इन संगठनों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई उद्योग स्थानीय मजदूरों को नहीं रखना चाहता, बल्कि जब स्थानीय स्तर पर उसे कुशल कामगार उपलब्ध नहीं होते हैं, तभी बाहरी मजदूरों के लिए जगह बनती है। ऐसे में इस कानून के कारण उनके मजदूर मिलने में समस्या हो सकती है। कामगारों के कौशल का निर्धारण किसी भी उद्योग का अपना मामला है, ऐसे में अब यह मामला सरकारी हो जाएगा और जहां तक कुशल हरियाणवी कामगार नहीं मिलने पर छूट की बात है तो इस निर्णय में लंबा समय लग सकता है जो किसी भी दृष्टा में उद्योग के हित में नहीं होगा। हरियाणा के पास भले ही प्राकृतिक संसाधन कम हैं, किंतु दिल्ली से सटे होने के कारण राजनेताओं का हमेशा ध्यान इस राज्य के औद्योगीकरण पर रहा और उसका प्रभाव है कि आज यह देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य है। उद्धरण के तौर पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल

A wide-angle photograph capturing a massive crowd of people walking along a paved street. The individuals, dressed in a variety of casual attire, are moving in the same direction, creating a sense of collective action. The scene is set outdoors under a clear sky, with some greenery visible in the background.

इह उद्योग इस कानून से पाप अपने यहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम रखने का प्रयास कर सकते हैं और मानवत्रम के बजाय मशीनों और आईटीफि शियल इंटेलिजेंस आदि को बढ़ावा दे सकते हैं। ध्यान रहे कि 10 से कम कामगार वाले उद्योग अधिकांश श्रम दियरे में नहीं आते हैं यानी र का स्तर सही रहेगा, यह कल है। एक अन्य तथ्य तय है कि नए उद्योग रुख करने में हिचकेंगे, प्रकार के रोजगार के तो कमी आएगी ही, इससे मग्नियर आर्थिक विकास भी सकता है। हरियाणा के श्री बुद्धत चौटाल भले ही के लिए हितकर बता रहे अर्थशास्त्र के हिसाब से भी आर्थिक विकास और ज्यादातर मामलों को रोजगार तथा स्तर दोनों मामले में ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। कों का मुक्त रूप से कहीं करने और उद्योगों का मैं पूर्ण स्वतंत्रता, उद्योगों का और लाभ प्राप्ति के साथ के आर्थिक विकास के नजरी है। ऐसा होने से राष्ट्र के संपूर्ण श्रमबल का मिलता है और वह इस बल देश के उपभोक्ताओं ही उत्पाद बना सकते हैं, य स्तर पर शिक्षा में किए वेश का सम्बुद्धित लाभ क स्तर पर भी ज्यादा सकते हैं। यह भी एक कि ये परिवर्तन तब लाए जा इज तमाम देशों रोजाना हो सरकार कानून विचार बा दलों चमत्कर्त धर्म नहीं खेत्रों उर्मल कई उद्धरण शिव नवारही रीडी रोजाना नकार एक हाल समझ प्रभाव ह जाएं एजेंट राष्ट्रीय प्रवृत्ति हरियाणा लाल लिए अवधि चौटाल के त वे आने जनाम

हैं जब एक ओर पूरे देश में भाँफ डूँग बिनेस को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य में भारतीय कामगारों के लिए वे एक अवसर किस तरह सृजित करते हैं, इस दिशा में भी भारत विदेश प्रयासरत है। ऐसे में, इस दिशा के बारे में हमें समग्रता से जानकरना चाहिए।

परी बनाम धरतीपुत्र = क्षेत्रीय द्वारा राज्य में अपनी राजनीति को लागू करना जरूरी हो गया था। देखा जाए तो यह मंजूरी दुष्ट चौटाला की पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक उपलब्धि है जिससे उनकी पार्टी का राज्य में जनाधार बढ़ेगा। इस कानून का प्रारूप जब पिछले साल जुलाई में तय किया गया था, उस समय भी इसको लेकर चौटाला ने ही राज्य के युवाओं को बधाई देते हुए इसे अपनी जीत के रूप में पेश किया था।

नने के लिए बाहरी बनाम युद्धों का मुद्दा उठाना कोई नया सरकारी नौकरियों और निजी की नौकरियों में स्थानीय वारों को वरीयता मिले इस पर अज्यों में आदेतन होते रहे हैं। एण के लिए महाराष्ट्र में नाना और उसके बाद महाराष्ट्र मर्मांग सेना ऐसे मुद्दों को उठाती है। हरियाणा का पूरा मामला भी उत्तर के मुद्दे पर चल रही उसी अत्यक्तक क्षेत्रवादी राजनीति का उद्घारण है जिसके प्रभाव में वे वर्षों में वृद्धि हुई है। झारखण्ड और कई राज्य भी इसके में आते दिख रहे हैं। याणा के इस कानून की तह में लेते ये क्षेत्रीय दलों और उनके के सामने राष्ट्रीय हितों और दलों के समर्पण की दुखद की तरफ भी इशारा करती है। या में सरकार का नेतृत्व मनोहर कर रहे हैं। राज्य के युवाओं के आरक्षण के द्वारा रोजगार के और बढ़ाने का वादा दुष्यंत ने विधानसभा चुनाव प्रचार रान किया था। सरकार के गठन ए भारतीय जनता पार्टी के साथ पर चौटाला के लिए अपना गर बचाने के लिए इस कानून

जनभागीदारी से जल निकायों का संरक्षण सुनिश्चित करे सरकार

जल के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जल के कारण ही आज मुख्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। वर्तमान समय में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन की समस्या विश्व समुदाय के समक्ष एक चुनौती बनकर उभरी है। पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन आज भी सबसे अधिक प्रासारित है। पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में सभी जीवित प्रजातियों को समान रूप से सम्मान देने के उदाहरण हैं। ऋग्वेदिक ऋचाओं में सभी के कल्पण की प्रार्थना की गई है। यही कारण है कि पृथ्वी पर न केवल मनुष्यों का, बल्कि सभी जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों का भी समान अधिकार माना गया है।

वेटलैंड्स हमेशा से भारत की सामाजिक-पारिस्थितिक प्रणाली का अभिन्न अंग रहे हैं। देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में फैले इन वेटलैंड्स द्वारा लाखों लोगों का जीवनयापन होता है। इनके संरक्षण की महत्ता तथा विषय की गंभीरता को समझते हुए सभी हितधारकों द्वारा इस दिशा में सतत प्रयास की आवश्यकता है। बचपन से कार्यक्षेत्र यमुना नदी के प्रवाह वाले कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और जगाधारी क्षेत्रों में होने के कारण वेटलैंड्स की बहुतायत उपस्थिति का गवाह रहा है। आज से तीन-चार दशक पहले तक इस क्षेत्र में तालाबों, बाबाड़ियों, कुओं, जोहड़ों तथा अन्य जल निकायों की भरभार थी। बरसात के दिनों में नदियों व नालों में आने वाली पानी पूरे क्षेत्र की धरती को आर्द्ध बनाए रखता था, जिससे साल भर के पानी की जलरूप पूरी हो जाती थी। आम जनमानस के जीवन में इन जल निकायों की महत्ता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हरेक शब्द अवसर पर ये पजनीय होते थे,

लेकिन बढ़ती जनसंख्या और अन्य मूलभूत विषयों के साथ ये निकायों का प्रवाह बहुत ज्यादा दिया गया, जिसके कारण सरस्वती के उद्गम स्थान नदी का पूर्ण प्राप्ति समय के साथ घट गया है। इसके पर आ गया था। इनके क्षेत्रों के द्वारा केंद्रीय जल शक्ति का विभिन्न प्रयासों से सरस्वती नदी का विकास हो गया है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक अवसरों का युक्त इस विर्ति पारिस्थितिकी और एकजुट होकर विभिन्न मिशन की व्यापकता आज नदियों द्वारा दिया जा रही है। इन नदियों की पारिस्थितिकी संरक्षण भीतर आशा और जागृत हुई है। इस विषय पर सहज विवरण संरक्षण एवं संवर्धन की जागृति है। नमामि गिरे गिरे कार्यक्रम है, जहां वेसिन प्रबंधन योग्य है। राष्ट्रीय स्वच्छता कार्य पूरे देश में विकास के लिए एक मॉडल निभा सकते हैं।

इस वर्ष सरल आधारित कार्यक्रम वेसिन विकास के लिए एक मॉडल निभा सकते हैं।

संस्थाया के लिए आवास तथा रुकर्तों को पूरा करने में तथा नी भागदौड़ में प्राकृतिक जल जाने-अनजाने में संकुचित कर ऐसे जल निकाय नष्ट होने लगे। इस स्थल आदि बद्री में जहां पहले हुआ करता था, दुर्भायवश जल निकाय समाप्ति के कगार हरियाणा की राज्य सरकार और मंत्री गणेंद्र सिंह शेखावत के हाईटेंड बोर्ड की स्थापना कर वेकास का प्रयास किया जा रहा की जीवनशैली, आस्थाओं एवं आत्मों वाले विशिष्ट संस्कृति से धारपूर्ण देश में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर किया जा रहा है। नमामि गंगे एवं विविधतापूर्ण पहलों से संरक्षण तथा पर्यावरण वलन को लेकर देशवासियों के विश्वास के साथ एक नई चेतना चिंतन ने देश को इस महत्वपूर्ण से एकजुट करने के साथ ही न के कार्यों को गति प्रदान की रान अपनी तरह का पहला ऐसा वेटलैंड संरक्षण कार्य को नदी नना का अभिन्न अंग बनाया गया गंगा मिशन द्वारा किए जा रहे नदियों और वेटलैंड संरक्षण के नेमवर्क के रूप में अहम भूमिका आंचल में बसे 50 से ज्यादा जिलों में स्थानीय गंगा प्रहरी प्रत्येक जिले में 10 से ज्यादा वेटलैंड्स की पहचान कर उनके विकास से संबंधित गतिविधियों पर कार्य करेंगे। इन गतिविधियों के आधार पर नमामि गंगे मिशन के माध्यम से वेटलैंड्स संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। वेटलैंड्स संरक्षण कार्य को कैच द रेन योजना से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि वर्षा जल को बेहतर तरीके से संरक्षित कर इसका समुचित तथा सार्थक उपयोग किया जा सके। इस योजना से न केवल झूजल का स्तर बढ़ेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली विनाशकी बाढ़ पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकेगा।

आज वेटलैंड्स पर बहुत सी जानकारी उपलब्ध है, रेगुलेटरी फेमवर्क भी मौजूद है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनको जपीनी स्तर पर मजबूत किया जाए और लोगों में इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। किसी भी अभियान की सफलता में जनभागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो उस योजना की सफलता का प्रमुख कारण भी। नमामि गंगे को भी सामुदायिक योजना की तरह लागू किया गया है जिसमें जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी है। आज जनभागीदारी के कारण वेटलैंड्स संरक्षण समेत घाटों की मरम्मत, तालाबों को पुनर्जीवित करना, नदियों के किनारे पौधरोपण, कचरे की सफाई जैसी समस्यों का समाधान सुनिश्चित हो सका है। समझना होगा कि वेटलैंड्स हमारी समृद्धि विरासत हैं तथा विश्व विरासत स्थलों की भाँति ही इनका संरक्षण आज समय की मांग है। आज वेटलैंड्स और नदियों के संरक्षण की दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। निश्चित रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग तथा जनभागीदारी द्वारा हम जल्द ही अधिकाधिक सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे।

जज यौन उत्पीड़न से जुड़े किसी मामले की सुनवाई करते हुए न तो किसी सी तरह की महिला विरोधी टिप्पणी करे और न ही दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले में दिया जिसमें हाईकोर्ट ने छेंडाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी थी कि वह पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब न केवल निचली बल्कि कई ऊपर की अदालतों में भी यौन उत्पीड़न को लेकर हल्का रुख देखने को मिला है। ऐसे मामलों में जजों के फैसलों तथा टिप्पणियों को लेकर समाज के संवेदनशील हल्कों में तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की गई, साथ ही न्यायालिका के एक हिस्से की सोच पर सवाल भी उठे।

न्याय के आसन से परे हटकर समाज के अन्य जिम्मेदार हिस्सों की ओर देखें तो ऐसे बयान थोक में मिल जाते हैं कि जिनमें महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर चरित्र प्रमाणपत्र बांटने की हड्डबड़ी नजर आती है। हालांकि भारत जैसे तेजी से बदलते समाज में महिलाओं को लेकर परस्पर विरोधी धारणाओं का मौजूद होना कोई अश्वर्य की बात नहीं है। हजारों साल की पितृसत्ता से उत्तरने वाले अनेक वैद्यतों द्वेषों वे-

संविधान निर्देश परिवेश में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के दरवाजे तो खुले, लेकिन परिवार और समाज के ढांचों में बदलाव की वह प्रक्रिया, जिसका काम उहें बराबर के इंसान के रूप में देखना संभव बनाना था, हमारे यहां काफी धीमी गति से आगे बढ़ती है। नतीजा यह कि महिलाएं पढ़-लिखकर अलग-अलग पेशों में ऊचे ओहदों पर पहुंचती गईं, लेकिन समाज उनके बारे में दिक्कानूसी ढंग से ही सोचता रहा। यह सोच कभी किसी नेता के बयान, कभी किसी अक्सर की हरकत और कभी किसी जज की टिप्पणी के रूप में सामने आकर देश को शर्मसार करती रहती है।

खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तजा निर्देश में उन वाक्यांशों के उदाहरण भी दिए हैं जो अदालती फैसलों में अक्सर स्थान पाते हैं और जिनसे आगे बचना जरूरी है। महिलाएं शारीरिक तौर पर कमज़ोर होती हैं और उहें सुक्ष्मा की जरूरत होती है से लेकर मातृत्व हर महिला का कर्तव्य है, पुरुष घर के मुखिया होते हैं और महिलाएं भावुक होती हैं इसलिए अक्सर ओवर सिएक्ट करती हैं तक ऐसा हर वाक्यांश पितृसत्तात्मक सोच की पूरी कहानी बयान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भले सिर्फ जजों के लिए जारी किया हो, यह पूरे समाज के लिए लिपिरेखा तो साब्दरेखा।

अपनी जमीन छोड़ती कांग्रेस, कभी अपने दम पर लड़ती थी चूनाव; अब सहयोगियों पर निर्भर रहने लगी है पार्टी

एक समय कांग्रेस ने इस पार्टी से समझौता करने से इन्कार कर दिया था। हाल में पीसी चाको ने इस्तीफा देकर केरल में भी कांग्रेस को झटका दे दिया है। चाको ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है। उन्होंने जिस तरह गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा किया, उससे उसकी और फजीहत ही हुई है। इसके पहले जी-23 गढ़ के तेवा भी प्रोश्व रुग्न

जा-23 गुरु के नता भा पराश्क रूप
से गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा
कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर
भाजपा का मुकाबला करने में
सक्षम दिखने वाली कांग्रेस अब
जिस तरह राज्यों में क्षेत्रीय दलों के
लिए अपनी जमीन छोड़ रही है,
उससे वह और कमज़ोर ही हो रही
है। कांग्रेस की यह कमज़ोरी
भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ
उर्ध्वी।



पांच राज्यों- बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव घोषित होने के पहले से ही भाजपा ने इन राज्यों में अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था। बंगाल में तो भाजपा ने पिछले देढ़ साल से ऐसा माहौल बना रखा है कि तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। तृणमूल नेताओं के भाजपा में शामिल होने का जो सिलसिला कायम हुआ था, वह चुनावों की घोषणा के बाद और तेज हो गया है। भाजपा में शामिल होने वाले तृणमूल के कुछ बड़े नेता भी हैं। इनमें दिनेश त्रिवेदी प्रमुख हैं। ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले सुवेंदु अधिकारी भाजपा में आने के बाद अब उन्हें ही नंदीग्राम में चुनौती दे रहे हैं। तृणमूल बंगाल में भाजपा की बढ़त रोकने के लिए हर तरह के काष्टकांडे अपना रही है। इनमें भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा भी शामिल है और पुलिस का दुरुपयोग भी। शायद इसी कारण चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस प्रमुख को हटा दिया।

ही नहीं दिख रही है।
बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें हासिल की थीं। यह अप्रत्याशित जीत थी। इस जीत ने भाजपा का मनोबल बढ़ाया। ममता दस सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके लिए तीसरी बार सत्ता हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि सत्ता विरोधी रुझान मजबूत होता दिखता है। भाजपा ने अपने चुनाव अभियान को प्रधानमंत्री मोदी की छवि और केंद्र सरकार के कामकाज पर केंद्रित किया हुआ है। इसके जवाब में तृणमूल के पास जनता को आकिञ्जन करने के लिए कुछ खास नहीं है। पिछले दस वर्षों में बंगाल की हालत में कोई बदला परिवर्तन नहीं आया है।

रकार ने केंद्र की योजनाओं
में अपने यहाँ लागू न करने का
काम किया, उसकी सफाई
उसके पास कहने के लिए
बुछ नहीं है। बंगाल में यह
लारणा मजबूत हुई है कि जो
प्रतीकरण की जो रणनीति
मना रखी थी, वह इस बार
माम आने वाली नहीं है। शायद
सीलिए ममता ने हिंदुओं को
झाने के लिए चंडी का पाठ
कथा तो मुसलमानों को संदेश

ने के लिए मस्जिद भी गई। अपने देश की विडंबना यह है जात-पांत और मजहब के गा है। इसके चलते कई बार के बजाय अन्य कारणों के होता है। ममता की मुस्लिम ब में भाजपा हिंदू मर्मों के जय श्रीराम नारे का इस्तेमाल दबाव में आई ममता खुद को हुई है। अन्य दल और विशेष वाम दल बातें तो सेक्युरिटीज रन उन्होंने कठुपंथी मौलाना दरगाह के पीरजादा अब्बास एवं याली मन से गवर्नर्चर्च क्य

ग्रन्थ चुनावों में भुनाने की कोशिश करेगी। इसमें कोई हर्ज भी नहीं।

लगातार कमजोर होती कांग्रेस भाजपा के लिए भले ही लाभकारी हों, पर देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं। एक समय जो कांग्रेस अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ती थी, वह अब सहयोगियों पर निर्भर रहने लगी है। उसकी यह निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में द्रमुक ने कांग्रेस को महज 25 सीटें दी हैं तो बगाल में वाम दलों ने 92। असम, करेल और पुदुचेरी में कांग्रेस अवश्य गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, लेकिन वह पहले जैसी सक्षम नहीं दिख रही। असम में जो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, वहां उसे पांच दलों से समझौता करना पड़ा है। इनमें सांप्रदायिक छवि वाली अजमल की पार्टी भी है। एक समय कांग्रेस ने इस पार्टी से समझौता करने से इन्कार कर दिया था। हाल में पीसी चाको ने इस्तीफा देकर करेल में भी कांग्रेस को झटका दे दिया है। चाको ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है। उन्होंने जिस तरह गांधी परिवार को कठघोरे में खड़ा किया, उससे उसकी और फजीहत ही हुई है। इसके पहले जी-23 गुट के नेता भी परोक्ष रूप से गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम दिखने वाली कांग्रेस अब जिस तरह राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी जमीन छोड़ रही है, उससे वह और कमजोर ही हो रही है। कांग्रेस की यह कमजोरी भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं।

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ने बताया उस टीम का नाम, जिसका वनडे सीरीज में पालड़ा रहेगा भारी

पट्टनामा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद पांच मैचों की टी-20 सीरीज काफी रोमांचक रही, जिसे भारतीय टीम ने 3-2 के अंतर से जीता। सीरीज के कई चौथावाह देखने को मिले, जब पहला मैच जीतने के बाद इंग्लैंड ने हूसरा मैच खेला था और फिर तीसरा मैच जीतकर चौथा मैच खेला था, जबकि आखिर मैच में भी महमान टीम के करारी हार जैलनी पड़ा। अब लय भारतीय टीम के साथ है। ऐसे में तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने बताया है कि किस टीम का पालड़ा वनडे सीरीज में भारी रहेगा।

विहार इंडिया (बीसीएल) में अग्रिका एवं बैर टीम के मेंटर के रूप में पट्टनामा और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने जागरण के साथ बातचीत में कहा कि टी-20 सीरीज में विराट कोहली की फॉर्म की बासपी बेहद ज़रूरी थी। इसका असर आइपीएल ही नहीं, बल्कि टी-20 विश्व कप पर भी दिखाया। विराट कोहली ने टी-20 सीरीज के फाइनल सेमेंट पूरी सीरीज में तीन अर्धशतक जड़ते हुए कुल 231 रन बनाए हैं। थोड़ा तक कि वे पहले मैच में खाता खाले पवरलियन लौटे थे। इसके बाद उन्होंने लय पकड़ी और दमदार पारियां खेलते हुए भारत को मैच जिताए। क्रिकेट में बढ़ रही स्लेजिंग के सबाल पर प्रसाद ने कहा कि क्रिकेटर मर्यादा के दायरे में रहकर कोई काम करें तो बेहतर होगा। 1996 विश्व कप के क्रार्टर फाइनल में आमिर सोहन ने मेरी गेंद पर फहले चौका जड़ा। फिर अगली गेंद की उसी जगह मानने के लिए इशारा किया। बैर एवं स्टेंजिंग किए मैंने इसका बदला आगामी गेंद पर उहाँे बोल्ड कर लिया। ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है। टी-20 टीम में तीन विकेटकापर रिष्प घंट, केलन राहुल और इशारा किशन की मीज़जूदी को सही ढहरते हुए प्रसाद के कहा कि इससे प्रतियोगी बढ़ेगी। पांच बल्लेबाजी के साथ इंडिया विकेटकापिंग के बारे रहे। राहुल क्रिस स्टर्ट के बल्लेबाज है। यह सभी को मालम है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैंने लौटेंगे। इशारा बल्दिया बल्लेबाज के साथ अच्छे फाईलर भी हैं। विहार उनका इस्तेमाल इधी तरह करेंगे। हालांकि, मेरा मानना है कि वह विकेटकापिंग में अपना सीधा प्रतिशत दे सकते हैं।

पहले वनडे गैरू में ये दो खिलाड़ी कर सकते हैं डेब्यू, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद टी-20 सीरीज का भी समाप्त हो गया है। अब दोनों देशों को तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में दो-दो हाथ करना है। कल यानी मंगलवार 23 मार्च से शुरू हो रही एकदिवसीय सीरीज के पहले मैच में भारत की फॉर्म की डोल्पी दो गेंदों पर हुई थी। लेकिन इसमें से दो ही खिलाड़ियों को पहले वनडे मैच में अपना गेंद भी है और कौन-कौन से नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इसके बारे में जान लीजिए।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वनडे सीरीज के लिए तीन नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिनमें एक बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर और एक गेंदबाज है। बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, ऑलराउंडर कृष्णा पांड्या और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पहली बार भारत की वनडे टीम में चुने गए हैं, लेकिन इसमें से दो ही खिलाड़ियों को पहले वनडे मैच में अपना गेंद भी है और उन्होंने को मौका मिल सकता है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की प्लेइंग इलेवन में फिट करना पसंद करते हैं। भारतीय टीम रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओराइंग जोड़ी के साथ मेंदान पर उत्तर सकती है, जबकि कप्तान किशन विराट कोहली के तीसरा स्पान पक्का रहेगा। चौथे स्थान पर सूर्यकुमार यादव को आजमाया जा सकता है। ऐसे में पांचवें स्थान पर केलन राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में जांग होगी। छठे नंबर पर रिष्प घंट पतं बैर विकेटकापर बल्लेबाज होंगे, जबकि सातवें नंबर पर मैच फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या का दावा पुकारा है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रीलंका के एक बल्लेबाज ने बनाए 70 रन और पूरी टीम पहली पारी में 169 रन पार देए

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ। मेजबान टीम ने टॉप जीतकर पहले गेंदबाजों करते हुए जूसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को पहली पारी में महज 169 रन पर ही ढेर कर दिया। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ़ एक अर्धशतक देखने को मिल जा लिया था। श्रीलंका ने 180 गेंद का समान कर दिया। विकेटकापर बल्लेबाज निरसेंग बिल्डे ने 76 गेंद पर 32 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं कर पाया। टीम के छह बल्लेबाज दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाए।

श्रीलंका क्रिकेट टीम का बुरा दूसरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। धरेल सीरीज में इंग्लैंड से हांस के बाद वेस्टइंडीज में भी वह खराब फॉर्म से उड़व नहीं पाई। दो मैचों की बीच पहले टेस्ट में खेलने उत्तरी श्रीलंका की टीम पहली पारी में महज 169 रन पर ही सिमट गई। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेवेट ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गेंदबाजों ने इसे सही साबित किया।

पहली पारी में श्रीलंका के बल्लेबाजों पर पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और केमार रोज भारी पड़े। दोनों ने मिलकर कुल 8 विकेट चटाकए। होल्डर ने 17.4 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। जबकि रोज ने 16 ओवर में 47 रन खर्च कर 3 बल्लेबाजों को आउट किया। करीम कार्नेवाल ने एक विकेट हासिल किया। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ़ एक अर्धशतक देखने को मिल जा लिया था। श्रीलंका ने 180 गेंद का समान कर दिया। विकेटकापर बल्लेबाज निरसेंग बिल्डे ने 76 गेंद पर 32 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं कर पाया। टीम के छह बल्लेबाज दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाए।

वनडे सीरीज आज से

भारतीय टीम घर में इंग्लैंड से 29 साल से नहीं हारी, उसके खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका

मंबड़। टी-20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच लिए तेज़ तेज़ है। सीरीज के तीनों मैच 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसेसमेंट के स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी रही थी।

पिछ्ली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है।

टीम

टीम इंडिया की यह साल दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई हैं। 9 में भारत को जीत मिली, मिली थी। फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड और नवंबर में

दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी रही थी।

पिछ्ली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है।

टीम इंडिया की यह साल दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई हैं। 9 में भारत को जीत मिली, मिली थी। फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड और नवंबर में

दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी रही थी।

पिछ्ली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है।

टीम इंडिया की यह साल दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई हैं। 9 में भारत को जीत मिली, मिली थी। फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड और नवंबर में

दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी रही थी।

पिछ्ली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है।

टीम इंडिया की यह साल दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई हैं। 9 में भारत को जीत मिली, मिली थी। फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड और नवंबर में

दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी रही थी।

पिछ्ली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है।

टीम इंडिया की यह साल दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई हैं। 9 में भारत को जीत मिली, मिली थी। फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड और नवंबर में

दोनों मैचों के बीच अब तक 18 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी रही थी।

पिछ्ली बार इंग्लैंड ने दिसंब